

समक्ष:- न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष / सदस्य म. प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर
भोपाल खण्डपीठ

प्रकरण क्रमांक :- PBR/निगरानी/बैतूल/शु-रा/2017/2040

1. पार्वती बाई बेवा स्व. पाडुरंग जाति माली उम्र 53 वर्ष
2. दुर्गादास पिता स्व. पाडुरंग जाति माली उम्र 30 वर्ष
3. अम्बादास पिता स्व. पाडुरंग जाति माली उम्र 26 वर्ष
4. देवीदास पिता स्व. पाडुरंग जाति माली उम्र 24 वर्ष
सभी निवासी धामनगावँ तहसील भैंसदेही जिला बैतूल म.प्र.
5. कुसुम लता पिता स्व. पाडुरंग जाति माली उम्र 28 वर्ष
सभी निवासी हिडली रोड आठनेर तहसील आठनेर जिला बैतूल म.प्र.

...अपीलार्थीगण

बनाम

द्वारका बाई जौजे बकाराम जाति माली उम्र 62 वर्ष
मेधनाथ मोहल्ला मुलताई जिला बैतूल म.प्र.

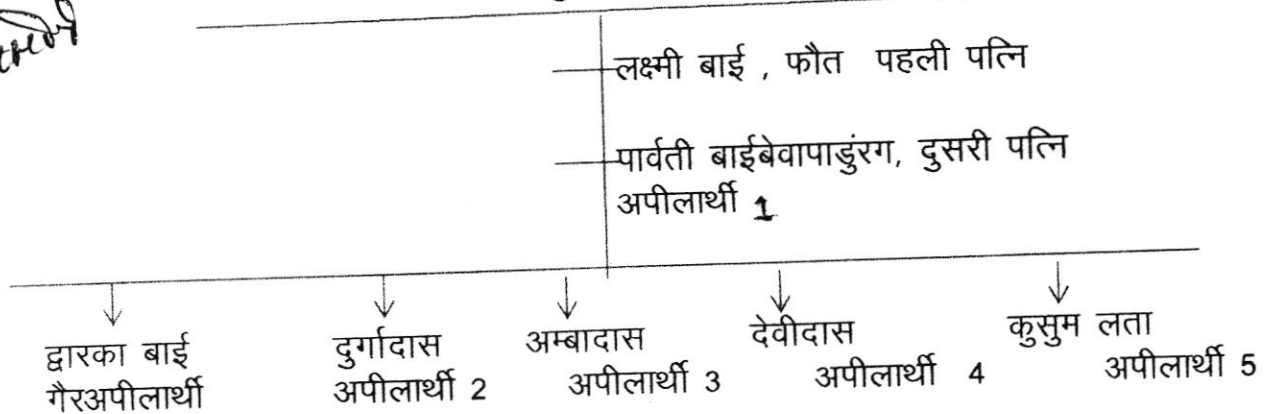
.. गैरअपीलार्थी

अपील अर्न्तगत धारा 44 - 2 म.प्र.भू रा. स. 1959

अपीलार्थीगण की ओर से विनय है:-

यह कि न्यायालय श्रीमानअपर आयुक्त नमर्दापुरम होशगांबाद म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 119 अ/ 6 2015.16 मे पारित आदेश दिनांक 09.05.17 से व्यथित एवं परिवेदित होकर श्रीमान् के माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत का जा रही है। मूल पुरुषपाडुरंग की खानदानी पैतर्क कृषि भूमि होने से इस प्रकरण मे निम्न लिखित वशांवली पर विचार करना वाद के निराकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

पाडुरंग पिता विठोबा, फौत मूल पुरुष



प्रकरण के तथ्य :

140

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/2040
स्थान तथा दिनांक

जिला बैतूल

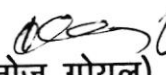
कार्यवाही तथा आदेश

फसकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

26-7-2017

आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 9.5.2017 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि 2/6 भाग का स्वामी अनावेदिका को माना गया है, और उसकी अपील भी निरस्त हो गई । वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, परंतु माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं है, इसलिये कार्यवाही स्थगित किये जाने का औचित्य नहीं है । तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होता है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष